17.15 hrs.

DEMANDS* FOR GRANTS (GENERAL) 1980-81—*Contd.*

MINISTRY OF ENERGY AND DEPARTMENT OF COAL (MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL)

MR. SPEAKER: The House will now take up discussion and voting on Demand No. 30 relating to the Ministry of Energy and Demand No. 82 relating to the Department of Coal (Ministry of Steel, Mines and Coal) for which 5 hours have been allotted.

Hon. Members whose Cut Motions to the Demands for Grants have been circulated may, if they desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the Cut Motions they would like to move.

Motions moved·

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1981, in respect of the head of Demand entered in the second column thereof against Demand No. 30 relating to the Ministry of Energy."

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India *to complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1981 in respect of the head of demand entered in the second column thereof against Demand No. 82 relating to the Department of Coal (Ministry of Steel, Mines and Coal).

Demands for Grants, 1980-81 in respect of the Ministry of Energy and Department of Coal (Ministry of Steel Mines and Coal) submitted to the vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demand for Grant on account voted by the House on 14-3-1980		Amount of Demand for Grant submitted to the vote of the House	
1	2	3		4	
		Revenue Rs.	Capital Rs.	Revenue Rs.	Capital Rs.
	MINISTRY OF ENERGY				
30.	Ministry of Energy . .	21,88,71,000	169,52,68,000	44,07,56,000	370,28,86,000
	MINISTRY OF STEEL, MINES AND COAL				
82.	Department of Coal . .	37,46,58,000	178,52,63,000	70,86,28,000	381,03,28,,000

***Moved with the recommendation of the President.**

श्री दौलत राम सारण (चूरू) : अध्यक्ष जी, मैं ऊर्जा मंत्रालय की अनुदान की मांगें जो इस सदन में विचाराधीन प्रस्तुत हैं, उनके सम्बन्ध में कहने के लिए खडा हुआ हूं ।

ऊर्जा मंत्रालय को गत वर्ष इस सदन के द्वारा जो धनराशि स्वीकृत की गई थी, उस धनराशि के अन्तर्गत जिन योजनाओं की स्वीकृति उनको यह मंत्रालय ठीक तरह से अंजाम नही दे सका है और अपने कार्यक्रमो को पूरा नही कर सकता है । ऊर्जा मंत्रालय उस धनराशि को सांगोपाग ढग से उपयोग करने में बिल्कुल असफल रहा है । मुझे खेद है कि यह मंत्रालय अपने सहयोगी मंत्रालयों का जिन मंत्रालयों से इनके कामकाज का सम्बन्ध है, उनका भी सहयोग प्राप्त नही कर सका है । उनका सहयोग प्राप्त करने में भी यह असफल रहा है । ये बार-बार इस सदन में जवाब देते रहे है कि बिजली इस-लिए ठीक तरह से पैदा नही की जा सकी कि रेलवे ने कोयला नही पहुचाया, स्टील मिनिस्ट्री ने ठीक समय पर नही दिया, इस लिए योजना पूरी नही हो सकी । इस तरह से यह मंत्रालय दूसरे मंत्रालयों को अपने सहयोग मे, विश्वास मे, नही ला सका है ।

17.17 hrs.

[SHRI GULSHER AHMED *in the Chair*]

सभापति जी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह आश्चर्य की बात है कि सरकार कोयला निकालती है, सरकार कोयला पहुचाती है और सरकार ही कोयला उपयोग करती है, लेकिन फिर भी बिजली पैदा नही होती । सब जगह सरकार है, कही कोई बीच मे नही है, लेकिन फिर भी कोयला आता नही । यह कह दिया जाता है कि रेल इस लिए नही चलती कि कोयला नही पहुंचा, डीजल नही पहुचा । पहुंचाने वाली सरकार की रेल, निकालने वाली सरकार और देने वाली सरकार, लेकिन इसके बाद भी जनता की यह हालत है कि बिजली नहीं, कोयला नही और डीजल नही । यह हालत इस सरकार की व्यवस्था की है, तो मैं ऊर्जा मंत्रालय के सम्बन्ध मे सबसे पहले यह कहना चाहता हू कि इस परिप्रेक्ष्य मे इनकी सारी कारगजारी को हम देख सकेगे ।

ऊर्जा मंत्रालय के अन्तर्गत नौ स्रोत है, जिनसे इनको ऊर्जा प्राप्त हो सकती है । उनमे सबसे मुख्य स्रोत है पानी का, दूसरा कोयले का, तीसवा सौर का, चौथा परमाणु का, पांचवां गोबर-गैस-प्लान्ट, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय विद्युत और वायु ऊर्जा--ये सारे स्रोत ऊर्जा प्राप्त करने के हैं और बाकी के स्रोत तो अभी खोजे जा रहे हैं । भूतापीय ऊर्जा तो केवल एक प्रयास है, अभी उसकी कोई संभावना नही लगती है । जहां भूमि से गर्म पानी निकलता है, उस से यह आशा करते हैं कि वहां से बिजली पैदा की जा सकेगी । इसी तरह से वायु स्रोत के अन्दर पहाड़ी क्षेत्रों में और दक्षिण के पठारों में पवन-चक्कियां स्थापित की हैं--जिन से ऊर्जा प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे है और छोटे-छोटे कुंओं के पम्पिंग सेट्स चलाने में कुछ सहायता मिली है । लेकिन कोई कारगर स्रोत अभी तक दिखाई नहीं पड़ा है । सौर ऊर्जा स्रोत की भी उज्ज्वल सम्भावना लगती है, लेकिन इस मंत्रालय के सामने ऐसा लगता है कि जितना कार्य इस सौर ऊर्जा के सम्बन्ध में करना चाहिए, उतना कार्य नहीं हो रहा है ।

आज प्रधान मंत्री जी ने भी इस सम्बन्ध में एक उत्तर देते हुए कहा था कि थोड़ा पानी गरम करने, रसोई में थोड़ा-बहुत काम करने और कही-कही खेतो की कोई चीज सुखाने के लिए सौर ऊर्जा के स्रोत का उपयोग होता है, लेकिन अभी यह सब प्रयोग की व्यवस्था में है, जब कि इस के बढ़ने की सम्भावना हमारे देश मे हो सकती है । इसलिए मेरा कहना है कि इस तरफ ज्यादा ध्यान दिया जाए ।

अब मैं परमाणु विद्युत की तरफ आता हूं--इसकी हालत बहुत खस्ता है । हमारे यहा परमाणु-विद्युत के तीन केन्द्र है---एक तारापुर में है जो तारापुर और अमरीका के बीच मे लटक रहा है, दूसरा मद्रास का है कल्पकम परमाणु विद्युत केन्द्र यह 235 मैगावाट यूनिट का है, यहा पर दूसरा यूनिट भी तैयार हो रहा है, तीसरा कोटा में रावत पार्टी में 220 मैगावाट यूनिट का है । चौथा नरोरा मे जो उत्तर प्रदेश मे है राजस्थान के कोटा मे जो एटामिल पावर प्लाट है उस की बडी दुर्दशा है, यह हर महीने या अधिक से अधिक दो महीने बाद बन्द हो जाता है । बन्द क्यो हो जाता है ? जितनी जानकारी मे प्राप्त कर सका हूं - आज तक इसका पता नही चल सका है कि इस के बन्द होने के क्या कारण है ? हर बार यह कहा जाता है कि अब यह ठीक चलेगा, लेकिन महीने-दो महीने के बाद फिर बन्द हो जाता है । इस से राजस्थान की विद्युत उपलब्धि पर बहुत बुरा असर पड़ता है । कोटा आज भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्र बन गया है । इस केन्द्र से बिजली न मिलने के कारण राजस्थान के सारे उद्योग लड़खड़ा गए हैं और राजस्थान की विद्युत उपलब्धि पर इस का बहुत बुरा असर पड़ा है। यही नही, उस से कई खतरे जो आणविक दृष्टि से पैदा होते है, उन की भी संभावना हो सकती है । इसलिए मैं इस मंत्रालय से निवेदन करना चाहता हूं, मेहरबानी कर के या तो इस को ठीक कीजिए या कोटा से उठाकर दिल्ली ले जाइये ताकि यहां रोज उस पर निगरानी रखी जा सके । राजस्थान की जनता इस से बहुत तंग हो चुकी है, राजस्थान की औद्योगिक क्षमता को, किसानों की क्षमता को इस ने नष्ट कर दिया साथ इस बात को कहना पड़ रहा है ।

जहां तक हमारे पारस्परिक स्त्रोतों का संबंध है, जैसे तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस---उस संबंध में हमारा देश बहुत सौभाग्यसाली है । कोयले के बहुत व्यापक भण्डार हमारे देश में है । 1 लाख 11 हजार 628 मिलियन मीटरिक टन कोयले के भण्डार होने का अनुमान है, जिसमें से 79,075 मिलियन मीटरिक टन गैर कोकिंग किस्म का कोयला है और 22500 मिलियन मीटरिक टन कोकिंग किस्म का कोयला है । हमारे इस कोयले का उपयोग बेहतरीन तरीके से थर्मल पावर प्लांट्स के लिए किया जा सकता था, लेकिन पहले इस की तरफ ध्यान नहीं दिया गया, हमारे योजनाबद्ध विकास में ऊर्जा उत्पादन के लिए पहले हाइड्रोइलैक्ट्रिक की तरफ ध्यान दिया गया, लेकिन उस को भी अधर में, बीच में, छोड़ दिया । जहां तक थे, थर्मल पावर प्लांटस का संबंध है---रेलें कोयला नहीं पहुंचा पा रही हैं, डीजल की उपलब्धि नहीं हो रही है जिस से हमारे थर्मल प्लांटस भी गड़बड़ा गये है और हमारी जितनी योजनायें है, सब लड़खड़ा रही रहीं हैं और देश में जगह-जगह जो हमारे उत्पादन के साधन हैं वे बुरी तरह से असफल होते नजर आ रहे हैं । इसलिय मैं कहना चाहता हूं कि पारस्परिक समन्वय और सहयोग की व्यवस्था की जाय, इस मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों के साथ सहयोग स्थापित होना चाहिये ।

17.25 hrs.

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair*]

इस की आवश्यकता है अन्यथा योजनाबद्ध विकास लड़खड़ा जाएगा । इधर देश में कोयले के साथ-साथ तेल और प्राकृतिक गैस के भी अच्छे भंडार बताए जाते हैं लेकिन जो सुनिश्चित भंडारों की क्षमता आंकी गई है, वह 300 मिलियन मैटिक टन के करीब है और देश के जो प्राकृतिक गैस के भंडार 73 बिलियन क्यूबिक टन के लगभग है और अभी जो दक्षिणी तट और बंगाल की खाड़ी और बम्बई में नये स्त्रोत मिले हैं, उन से हम आशा करते है कि तेल और गैस के प्राकृतिक साधनों के अधिक अच्छे भंडार मिल सकेंगे । इस तरफ सरकार का ध्यान अधिक जाना चाहिए ताकि हमें ऊर्जा के अधिक स्त्रोत मिल सके लेकिन मुझे खेद है कि यह मंत्रालय इस तरफ जितना ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं दे सका है ।

अब मैं पन-बिजली की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । पन-बिजली की स्थिति यह है कि देश के जलीय संसाधनों से लगभग 400 टी० लब्ल्यू० टी० वार्षिक ऊर्जा पैदा की जा सकती है लेकिन इसमें से केवल 10 प्रतिशत का उपयोग किया गया है । इस तरह से इन व्यापक संसाधनों का पूरा उपयोग करना चाहते हैं, तो इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए जबकि सरकार का ध्यान पूरी तरह से इस तरफ नहीं गया है । हमारे पास बहुत सारे प्राकृतिक साधन हैं । हमारा बहुत सारा पानी बह कर नदियों के द्वारा समुद्र में चला जाता है और हम यह भी देखते हैं कि अरबों रुपये की जन धन की हानि प्रति वर्ष हमें बाढ़ों के कारण उठानी पड़ती है लेकिन इस पानी का उपयोग हम सिंचाई और विद्युत उत्पादन में नहीं कर पाए हैं और यह अभी तक तबाही का कारण बना हुआ है । मैं ऐसा समझता हूं कि परस्पर मंत्री स्तर पर और मंत्री मंडलीय स्तर पर सम्पर्क और योजना की उपेक्षा का परिणाम यह है । ऐसा मुझे नजर आता है और मैं यह निवेदन करूंगा कि इस तरफ़ अधिक ध्यान दिया जाए ताकि इन प्राकृतिक साधनों का उपयोग हमारे विकास के कार्यों में हो सके । अगर योजनाबद्ध तरीके से सब से पहले बिजली, पानी और सड़क केवल इन तीन चीजों की तरफ ध्यान दिया जाता तो आज देश का नकशा कुछ और ही होता । समग्र पानी को इस्तेमाल करने की तरफ़ ध्यान दिया जाए और उस के लिए आप योजना बनाएं । आप पानी को खेतो तक पहुंचाएं और बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल में लाएं तो इस से लोगो की बहुत फ़ायदा होगा । इसके अलावा जमीन के नीचे जो पानी है, उस को भी निकाला जाए उस से बिजली पैदा की जाए, तो अधिक उत्पादन हम कर सकते हैं और इस से देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, उस का समाधान भी कर सकते हैं और देश में जो आज अभाव की स्थिति है, उसको भी मिटा सकते हैं लेकिन मुझे अफसोस है कि योजना-निर्माताओं ने उस तरफ़ उतना ध्यान नही दिया जितना प्राथमिकता के हिसाब से देना चाहिए था । उसी का परिणाम आज हम लोग भुगत रहे हैं । देर आयद दुरुस्त आयद, अगर अब भी दुरूस्त हो जाए, तो भी मैं समझता हू कि हम अपने संसाधनों का अधिक उपयोग कर सकते हैं ।

ग्रामीण विद्युतीकरण के नाम पर जब हम स्थिति देखते है, तो हमारे सामने सारा चित्र स्पष्ट हो जाता है कि ध्यान किधर है । आप यह देखिये कि देश के अन्दर 80 प्रतिशत लोग गांवों में बसते हैं । 5,76,000 गांव हमारे देश में हैं लेकिन 33 वर्ष की आजादी के बाद केवल 2,55,735 गांवों को ही बिजली दी गई है और 39,99,173 पम्पिंग सैटों को बिजली दी गई है । यह नकशा हमारे सामने है । केवल 15.5 या 15.6 परसेन्ट बिजली गांवों को दी गई है । देश की यह स्थिति यह बताती है कि हमारा ध्यान किधर है ? आप औद्योगिक क्षेत्र को करीब 60.6 परसेन्ट बिजली देते हैं, रेलवे को 3.8 प्रतिशत और अन्य को 4 प्रतिशत बिजली देते हैं । छोटे उद्योगों को आप केवल 6 प्रतिशत बिजली देते हैं ।

इस प्रकार हम देख रहे हैं कि बिजली उत्पादन में कमी हो रही है । बिजली के उत्पादन की ओर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा जितना कि दिया जाना चाहिए । हमारे यहां प्राकृतिक साधन

[श्री दीनत राम सारण]

प्रचुरता में होते हुए भी, अन्य साधन भी उपलब्ध होते हुए हमारा जितना ध्यान उधर होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है । उसको हम प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं दूसरी तरफ जो हमारी उत्पादित ऊर्जा है उस ऊर्जा का भी हमने इस तरह से वितरण किया है कि उसमें हमने बहुसंख्यक लोगों को उपेक्षा की है । हमारे देश का वह क्षेत्र, वह उद्योग जिस पर हम बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, उसको हम केवल 15 प्रतिशत बिजली देते हैं । जिस क्षेत्र पर हमारी बहुत अधिक जनसंख्या निर्भर करती है, जो क्षेत्र इस देश में 33 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन करता है उसको हम केवल 15 प्रतिशत बिजली देते हैं और जो क्षेत्र 10 या 11 हजार करोड़ रुपये का वार्षिक उत्पादन करता है उसको हम 60.6 प्रतिशत बिजली देते हैं । यह हमारी स्थिति है । मैं औद्योगिक क्षेत्र को पनपाने के विरुद्ध नहीं हूं । लेकिन देश की जो तात्कालिक आवश्यकता है जिससे आप आदमी का जीवन स्तर ऊंचा उठता है, रोजगार मिलता है उसको हमें प्राथमिकता देनी चाहिए । देश के अन्दर उत्पादन बढ़ाने और लोगों में अभाव को दूर करने के लिए मैं खेती को प्राथमिकता दिया जाना आवश्यक समझता हूं । इसकी तरफ ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है ।

जो कार्यक्रम बताया जाता है उस कार्यक्रम को देखते हुए मुझे नहीं लगता कि गांवों की तरफ ध्यान दिया जाएगा । जैसा कि मैंने अभी बताया अभी तक आधे गांवों में भी बिजली नहीं है । यह बताया जाता है कि अगर 3,366 करोड़ रुपये हों तो 1994-95 तक सब गांवों को बिजली दे सकते हैं । यह भी कहा जाता है कि इस मंत्रालय की ओर से अगर कुछ अधिक धनराशि दी जाए तो आधे के करीब गांवों को 1984-85 तक विद्युत प्रदान की जा सकती है । लेकिन साथ ही यह भी कहा जाता है कि यह धनराशि भी उपलब्ध होने की आशा नहीं है । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह धनराशि उपलब्ध हो सकती है । बहुत से फिजूल के कामों में तो धनराशि खर्च कर देते हैं लेकिन देश के बहुसंख्यक लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए राशि उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं । मै ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इसकी तरफ गंभीरता से ध्यान दें और गांवों को अधिक बिजली देने के लिए अधिक धनराशि दें । अगर खेतों तक अधिक बिजली पहुंचेगी तो अधिक रोजगार के साधन बढ़ेंगे और देश में अधिक उत्पादन होगा । आज अनेक कृषि उत्पादों के लिए बाहर दौड़ रहे हैं । हमारे यहां दालों का अभाव है, तेलों का अभाव है । यह स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी अगर खतों के लिए पूरी बिजली नहीं मिलेगी, पूरा पानी नहीं मिलेगा । आज गांव के लिए यातायात के साधन नहीं हैं । आपके पास बिजली पैदा करने के साधन हैं । आप अधिक बिजली पैदा कीजिए अधिक गांवों को दीजिए हम यहां से उसके लिए मंजूरी देने के लिए तैयार हैं ।

गांवों के विद्युतीकरण के लिए एक बात कही जाती है । उसके लिए तीन प्रकार के कार्यक्रम चलते हैं । तीन प्रकार के दृष्टिकोण अपनाये जाते हैं । एक राज्य का सामान्य विकास कार्यक्रम है । दूसरे कृषि पुनर्वित्त विकास निगम, वाणिज्यक बैंक, भूमि विकास बैंक आदि वित्तीय संस्थाएं ये तीनों मिलकर कार्यक्रम के लिए धन देती और इस कार्यक्रम को बनाने के लिए दो उद्देश्य सामने रखे जाते हैं ।

एक लघु सिंचाई का और एक ग्रामीण उद्योगों का इस कार्यक्रम की क्या स्थिति है यह मैंने अभी आपको बता दिया है । बिजली कृत गांवों में खेती के लिये जो बिजली दी जाती है वह मंहगी दी जाती है, रेट उसका बहुत हाई है और उद्योगों के लिए जो बिजली दी जाती है वह सस्ती दर पर दी जाती है । खेत तक बिजली पहुंचाने के पैसे किसान से लिए जाते हैं । अगर एक किसान एक अपने खेत के कुंए पर बिजली ले जाना चाहता है तो राज्य का बिजली बोर्ड साढ़े आठ सौ रुपया फी सम्मा चार्ज करता है । मोटर भी दो सौ रुपये का होता है जो बिजली बोर्ड किसान से लेता है । किसान से पैसे लेने के बाद भी मोटर किसान का नहीं हो जाता है, वह बिजली बोर्ड का ही रहता है । मोटर का तार तोड़ दिया, नाम से सैकड़ों झूठे केसेज राजस्थान में किसानों के खिलाफ चलाए गए हैं । जब बिजली वह मांगता है तो बिजली की चोरी का केस उस पर लगा दिया जाता है । यह हालत आज गावों की है । इन गांवों की विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत गावों में खम्भे लगा दिये जाते है लेकिन आगे बिजली पहुंचाने के लिए पैसे का अभाव बता दिया जाता है ------

श्री मनी राम बागड़ी : (हिसार) कोरम ही नहीं है । आप कैसे हाउस को चलायेंगे कोरम को आप देखें । ट्रेजरी बेंचिज सब खाली है ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) साढ़े पांच बजे के बाद यह कोरम का सवाल नहीं उठाना चाहिये।

MR. DEPUTY-SUEAKER: Generally this point is not raised. Mr. Man Ram Bagri, you know....

SHRI MOOL CHAND DAGA: At 5.30 p.m. this point should not be raised.

श्री दौलत राम सारण : जो बिजली दी जाती है वह सही ढंग से नहीं दी जाती है । बिजली बोर्ड भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है । किसानों को बड़ा परेशान किया जाता है । बिजली की चोरी के झूठे मुकदमें किसानों पर लगा दिए जाते है । बार बार बिजली गायब होती रहती है । इसकी वजह से किसानों की जो मोटरें होती है व जल जाती है और उनको भारी नुकसान होता है । बिजली उसको बहुत ही थोड़ी मात्रा में दी जाती है । किसान खेत बोता है तो उस समय उसको बताया नही जाता है कि इतनी बिजली देगें । जब वह फसल को चूकता है उसके बाद कटौती कर दी जाती है । यह जो कटौती की जाती है उसकी वजह से किसान की खड़ी फसल जल जाती है । इस प्रकार की कटौती के कारण लाखों मन अनाज नष्ट हो गया है पिछले वर्ष । यह कोई कारखाना नहीं है कि जब मर्जी आई तब बिजली बन्द कर दी । अगर फसल के पहले के समय पर एक पानी नहीं दिया जाएगा या दो पानी नहीं दी जाएगी तो पूरी फसल नष्ट हो जाएगी और नष्ट हो जाती है । तब कुछ भी नहीं मिलता है । घास भी नहीं मिलती है । यह दृष्टिकोण बिजली विभाग के लोगों के दिमाग में नहीं है । इस हद तक उपेक्षा किसानों की हो रही है।

ऊर्जा मंत्रालय की स्थिति यह है कि जो बिजली दी जाती है उसका रेट अलग अलग जगहों पर अलग अलग है । राजस्थान में मिनिमम चार्ज किसान को देना ही पड़ता है वह बिजली जलाए या न जलाए । उतने पैसे तो उसको हर हालत में देने ही पड़ेंगे । बिजली कट सरकार ने या बिजली बोर्ड ने भी कर दिया तब भी उसको मिनिमम चार्ज के पैसे देने ही पड़ेंगे और अगर नहीं देता है तो उसके खिलाफ वारेंट निकाल दिए जाते हैं । यह अजीब स्थिति है । वह निवेदन करने जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती और कहा जाता है कि यह कमर्शियल डिपार्टमेंट है। इस तरह से कमर्शियल लाइन के आदमी कंज्यूमर्स के साथ बिजिनेस नहीं करते हैं, उनके साथ इस तरह से डील नहीं करते हैं जिस तरह से यह डिपार्टमेंट करता है । इन बातों पर गौर करने की आवश्यकता है ।

देश में 31 हजार मैगावाट बिजली का उत्पादन होता है जिसमें से 60.6 प्रतिशत बिजली तो उद्योगों को दी जाती है और केवल 15.6 प्रतिशत ही किसानों को दी जाती है । गांवों के साथ यह भेदभाव, गांवों की यह उपेक्षा समझ में नहीं आती है । धन्ना सेठों को अधिक बिजली तथा तरह तरह की सुविधायें दी जाती हैं, उनको लाभ पहुंचाने की चेष्टा की जाती है । लेकिन गरीब किसान अपने कुएं के लिये बिजली के लिये तड़पता है, उसको बिजली नहीं दी जाती । इसलिये यह उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसको बन्द करना पड़ेगा ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि यह डिपार्टमेंट अनेक निगमों, बोर्डों और समितियों में बंटा हुआ है और एक दूसरे के साथ उनका कोई समन्वय नहीं है । सब अपना अपना ऊंट हांकते हैं । इसलिये इसमें को-आर्डिनेशन और को-आपरेशन की आवश्यकता है । नहीं तो योजनाएं पड़ी रहती हैं । मुझे पता है कि यह योजनाओं की तरफ बरसों ध्यान नहीं देते और जब ताकीद की जाती है तो वदर निकाल कर स्टेट को वापिस भेज देते हैं।

राजस्थान में पलाना लिगनाइट पावर प्लान्ट के लिये योजना भेजी गई स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से । छठी लोक-सभा में मैंने प्रश्न भी किया था, उस समय मुझे जवाब दिया गया कि राजस्थान में बिजली सरप्लस है, इसलिये आवश्यकता नहीं है इस प्लान्ट की अभी । लेकिन राजस्थान की क्या हालत है, वह तो आप स्वंय जानते हैं कि किस तरह से वहां बिजली के अभाव की स्थिति है । मैं कहना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान के लिये पलाना लिगनाइट पावर प्लान्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है, उसको तुरन्त स्वीकृति दी जानी चाहिये और उसके लिये धन भी सहायता स्वरूप दिया जाना चाहिये ।

इसी तरह कोटा का जो थर्मल पावर प्लान्ट है, उसके निर्माण में बहुत ढील चल रही है, उस पर ताकीद करनी चाहिये । राजस्थान पिछड़ा हुआ है, खेती में भी पानी बाहर से आता है दूसरे प्रान्तों से और बिजली भी दूसरे प्रान्तों से आती है और उसमें जब आपकी सहायता रहगी, तभी काम हो सकता है ।

मै मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं कि वह अपने उत्तर में यह बताने का कष्ट करें कि आपके जो विभिन्न ऊर्जा स्रोत हैं, उनके उत्पादन पर प्रति यूनिट कितना लागत खर्चा आता है और उसमें कन्ज्यूमर्स से आप क्या चार्ज करते है कितना मुनाफा बीच में रखते हैं और प्रशासनिक व्यय उसपर कितना पड़ता है, यह सब बतायें । यह आंखें खोलने वाली बात होगी । मैं खुद यह बात न कहकर आपसे पूछना चाहता हूं मुझे उम्मीद है कि आप जवाब देते हुए अवश्य इसका उल्लेख करेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने कई बार घंटी बजा कर मुझे जो बोलने का समय दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मै मंत्री महोदय को कहना चाहता हूं कि गांव की, गरीब की उपेक्षा बन्द करो । हिन्दुस्तान गांव में बसता है, गांधी जी कहकर गये हैं । इसलिये खेत और गांव की तरफ ध्यान दो । खेत हरा होगा तो देश हरा होगा, खेत सूखा होगा तो सारा देश भूखा होगा । इसलिये बिजली दो, काम दो, सस्ते रेट पर दो और किसान को खुशहाल बनाओ । बेरोजगारी पर हमला करना है, अभाव मिटाना है तो खेत की तरफ बिजली का मुंह मोड़ दो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. S. B. Chavan.

SHRI S. B. CHAVAN (Nanded): May I request you to give me time to-morrow because I am not feeling well now.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay.

SHRI ANANDA GOPAL MUKHOPADHYAY (Asansol): Mr. Deputy-Speaker, I rise to support the demands placed by the hon. Minister before the House. According to my consideration, it is one of the most important subjects that we are discussing today. Much depends upon the development of energy in our country—the development of industry, the development of agriculture and the total economic development of the country. If you look at the performance of the generation of power in our country in 1976-77 the performance was 56 per cent. If you look at it again in 1979, it had gone down to 45 per cent. From 56 per cent it has gone down to 45 per cent. As a result what happened? The entire production in the industry was on the decline—the production of steel, the production of coal, the production of cement and also the production of agricultural products had declined. This was the position at a stage when Congress assumed power in 1980. After that there has been a tremendous effort to develop power generation. In this House, we have observed the greatest concern of the Prime Minister about the generation of power in our country and for that certain positive measures have been certain positive measures have been co-ordination with the Railways, to have co-ordination with other respective Departments so that the coal can reach power houses in our country. If you look at the figure of the rate of movement, or the movement of coal to the power stations, our daily requirement for the power stations is about 1,900 wagons per day. It came down to 1,800 wagons per day earlier. Consequently, the position of the stock in the power Houses in many plants was very much less. Sometimes, the power Houses could not work. In such a stage, for total co-ordination a Committee headed by the Finance Minister has been formed. It has considerable importance and as a result the power generation from 45 per cent efficiency has gone up to 48 per cent efficiency. The power plants in our country for want of constant care for three years have suffered very much. For lack of proper maintenance there were frequent break-downs. The optimum capacity production became completely bleak. What are the measures taken by the present Government? To-day, an overall training of the officers and the operators had been organised. Four institutes have been built in our country to train the officers and to train the executives. This has also started giving result. As you know, the present concept of the Government is to meet the power crisis. To do so, Government have to start super power stations in the country. Government has decided to have super power station at the pit-heads—where there is coal, where other infra-structural facilities are available, where water is available. Government is going to have super power stations located over such place. I would suggest that super power stations should be absolutely in the central sector because required technology is complicated and sophisticated and sufficient training in the matter of installation and operation of these power stations is not with the State Electricity Boards in our country. I would recommend that super power stations should be built up by the central sector, with proper supervision and with the help of proper technical personnel in our country. While doing so, we will have to take care about the running of the power stations by State electricity boards. The State electricity boards in many States are more interested in grabbing more power than to generate more power. It is a body where they do not like to generate more power but they like to have politics.

Take for instance the State of West Bengal. The eastern region is suffer-

ing maximum for want of power because in planning for additional capacity to be built up, there was a complete holiday. In the last three years—excuse me if I am a little critical about the functioning of the State electricity Board in West Bengal. I am compelled to do it. Why? A big project was okayed at Kolaghat as far back as 1974. After that, good progress was made up to 1977, but after 1977, what happened? Is the civil engineering work being done? The machines that have been delivered are getting junk completely. The machinery are in such a bad shape even today that if it is commissioned after three or four years, you will see that the power plant is not functioning and there is leakage and breakdown any moment, any time. What is the State Government doing? The State Government is sleeping over the situation.

What is the power position in West Bengal? In the industrial areas, lay off of industrial workers has become a permanent feature. The worst hit are the working population in the jute, engineering, textile, steel and other industries. What about the power plants maintained by them at Durgapur? It is a State Government project and they are doing it themselves. But what is the output? Till the other day, the transfer of power to Calcutta was zero. What is the total time of load-shedding in Calcutta area? My hon. friends opposite know it very well. When power comes, the children shout, "Jyoti Babu agaya" and when power goes, day in and day out, during night and day, in hot summer, the children shout, "Jyoti Babu chala gaya". It has become a joke in West Bengal, because it is not properly taken care of;

So far as DVC is concerned, upto 1976-77, can my friends opposite say that the production was not up to 900 MW? What happened to DVC in 1977-78, 1978-79 and 1979-80? As I said in the beginning, those people who were in charge were not interested in generating more power. They were interested in grabbing more power. DVC which was producing up to 900 or even 1000 MW has gone down to 340 MW. It is not flattery, but I am saying a fact—after the Congress has come to power, the Chairman of DVC would not have visited DVC so many times in a year as has been visited by the Power Minister. Chanderpur is an isolated place and the station there is not working. I have seen the Minister going there four times. I am not making flattery of him. It is a fact. He is trying his best. The challenge is before him and he is fighting. But there must be one thing done for the DVC. He must find a proper person for the DVC, a challenging dynamic executive who can enthuse the workers and the officers, provide better maintenance, better production and a better coordination in this matter. I am pretty sure that DVC would also come up after proper modifications and other things.

As regards electricity generation, we, in our country, are still depending on traditional methods. We are going on for thermal power generation. We are trying to go on in a big way for hydro-generation. But we should go in for nuclear power generation. We should also go in for development of solar energy in our country and tidal power. I would urge upon the Minister to kindly employ all his machinery in that direction. I know that in the Ministry works have been divided in those categories and this time the Budget has given lot of incentives to the scientists of our country to go in for research work. There will be a complete change if we tap and commercialise the solar energy and also harness the tidal power in our country.

While doing so, I would advise the Minister on a few other points. There should be proper legislation in the hands of the Government to take over those state electricity boards which

[Shri Ananda Gopal Mukhopadhyay]

are not functioning properly, which have got additional sanction of new projects in their hands but are sleeping over them and where the progress for construction of the power stations is not satisfactory. Apart from that, I would also suggest that in our present planning as has been envisaged by the Minister, we should take over the super power stations in the Central Sector. We cannot leave the development of the country, industrial and agricultural development of the country in the hands of those who would be politicking in the State sector. All officers and men must be thoroughly trained in doing that job

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr Mukhopadhyay, you can continue tomorrow.

A list showing the numbers of cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Energy and Department of Coal treated as moved on the basis of the slips received from Members concerned, has been put up on the Notice Board for the information of Members.

In case any Member finds any discrepancy in the list, he may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE (Panskura): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure in rural electrification (1)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to make liberal grant for the Rural Electrification schemes in West Bengal (2)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to revitalise the administration of the Damodar Valley Corporation and make it efficient so that its installed capacity is fully utilised (3)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to improve the performance of the Damodar Valley Corporation and make it efficient so as to stop its frequent tube-leakage, etc. (4)].

"That the demand under the head Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to utilise the installed capacity in thermal power stations under the Central Government management (5)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re 1"

[Failure to prevent theft to electricity in transmission to the tune of 20 per cent in the country (6)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to realise huge arrears of dues from the consumers of electricity amounting to nearly 80 crores of rupees (7)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Intention to bring the power generation and supply under the purview of the Centre (8)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to make serious and determined efforts to find alternative power sources such as solar energy, tidal energy etc. (9)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to sanction the Silent Valley Project in Kerala (10)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to give liberal financial assistance to State electricity boards for production and distribution of more power (11)].

SHRI R. K. MHALGI (Thane): I beg to move:—

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to clear various power projects submitted by Maharashtra Government (12)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced by Rs. 100"

[Delay in clearance of Power Generator Projects in Maharashtra (21)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced by Rs. 100"

[Inefficient working of various Electricity Boards in the country especially in Maharashtra Electricity Board (22)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced by Rs. 100"

[Need to explore alternative energy sources for agriculture in view of increase in rates of power supply (23)].

SHRI BHOGENDRA JHA (Madhubani): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to repair and activise the generating machines of Darbhanga Electricity Company, Darbhanga Raj and Sakri Power House in Darbhanga District of Bihar (17)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to generate electricity upto to rated capacity and lack of concrete plan for the same (18)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to plan and execute the construction of Multipurpose High Dams at Barahkshetra and other points of river Koshi capable of producing 7000 megawatts of hydel ([19)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to construct Multipurpose High Dams at Nauthar on river Bagmati, at Sisapani on river Kamala and at Bandev on river Sone (20)].

SHRI K. A. RAJAN (Trichur): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to evolve a long term strategy on power conservation (38)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to implement the recommendations of the Study Group on Energy, constituted by the Planning Commission (39)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to give preference and priority for hydro-power generation (40)].

[Shri K. A. Rajan]

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to sanction the Silent-Valley Hydro Project in Kerala (41)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to clear the third stage Idikkli Hydro Project of Kerala (42)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to bring down transmission losses to the minimum (43)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to provide adequate financial assistance for various States Electricity Boards to start new generation projects (44)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to make efforts for alternative power resources like Solar and tidal (45)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to evolve a comprehensive scheme for rural electrification (46)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to supply quality coal to thermal plants (47)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to run the various thermal plants under the Central Authority to its optimum capacity (48)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to attend to regular maintenance of the various thermal plants under the Central Authority (49)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to establish thermal plants at coal pit-heads (50)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to realise huge arrears due from the high tension consumers (51)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to supply adequate power to the citizens of Delhi by the Central Authority (52)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to prevent theft of power by big industrial consumers (53)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to evolve an industrial wage policy for electricity workers (54)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to evolve wage standardisation in power industry (55)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to revitalise the working of the Damodar Valley Corporation (56)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to look into the occasional failure of electricity under the DESU (57)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Intention to bring power generation under the Central Authority (58)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Intention to take over the State Electricity Boards (59)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Intention to grant new licences for power generation in the private sector (60)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Intention to liberalise sanctioning of captive power stations in various industrial units (61)].

SHRI SATYANARAYAN JATIYA (Ujjain): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced by Rs. 100".

[Need to expedite the work on National Power Grid (93)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced by Rs. 100".

[Need to make Central Electricity Authority more effective (94)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced by Rs. 100".

[Need to expedite the survey of new hydel and thermal power production schemes (95)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced by Rs. 100".

[Need to start the work on Narmada Sagar Project (96)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced by Rs. 100".

[Need to expedite the erection work of thermal power schemes with proper care (97)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced by Rs. 100".

[Need to make Rural Electrification Corporation more efficient (98)].

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipir): I beg to move:

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to electrify the villages of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections (119)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure in rural electrification (120)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to utilise the installed capacity in the thermal power stations under the management of the Central Government (121)].

[Shri Ram Vilas Paswan]

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to prevent theft of electricity in transmission to the tune of 20 per cent in the country (122)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to realise huge arrears of dues from the consumers (123)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1

[Need to bring the power generation and supply under the purview of the Central Government (124)].

"That the demand under the head 'Ministry of Energy' be reduced to Re. 1"

[Failure to find alternative power sources (125)].

SHRIMATI GEETA MUKHERJEE: I beg to move:

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to supply soft coke to various parts of the country including West Bengal (1)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to remove contract system of labour in various coal mines (2)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to take up new coal mines in various parts of the country including that of Bankura (3)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to break the vicious circle of coal shortage, wagon shortage and the resultant power shortage in the country (4)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to prevent underground fire in Jharia and other coal fields (5)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to implement National Coal Wage Agreement in all the coal mines under Coal India Ltd. (6)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to increase the production of Coal from underground mines in Eastern Coal Fields Ltd. and Bharat Coking Coal Ltd. (7)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to prevent sinking of land in coal mines of Asansol-Raniganj area of West Bengal (8)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to improve medical facilities and water supply to coal mines, under Central management (9)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to root out corruption and to punish guilty officers of various coal companies, under Central management (10)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to check the alarming rise of accidents in Eastern coal fields Ltd. the biggest company under Coal India Ltd. (11)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to punish the officers responsible for various mine accidents as a result of inquiries made by the Director General of Mines Safety (12)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to implement the recommendations of various safety conferences in relation to coal mines (13)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to punish officers who were held responsible for the coal mines disaster at Silwara, Madhya Pradesh, by the Court of Enquiry (14)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to supply adequate power to coal mines leading to sharp fall of production (15)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced to Re. 1"

[Failure to supply adequate and good quality coal to thermal power stations, affecting power production (16)].

SHRI R. K. MHALGI: I beg to move:

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced by Rs. 100."

[Large scale absenteeism and surplus workers in CIL (19)].

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced by Rs. 100."

[Need to check the loss of rupees one crore a month in CIL (20)]

"That the demand under the head 'Department of Coal' be reduced by Rs. 100".

[Need to look into the difficulties of cotton textile mills in Bombay due to acute shortage of coal (21)].

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House stands adjourned to meet tomorrow at 11 A.M.

18.00 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Thursday, July 10, 1979/Asadha 19, 1902 (Saka).

GMGIPND—L—1267LS 13-9-80—890